

भारत के उच्चतम न्यायालय में
अपराधिक मूल / अपीलीय अधिकारिता

पुनर्विलोकन याचिका (आप.) क्रमांक – 591 / 2014

में

अपराधिक अपील क्रमांक – 338 / 2007

साथ में

रिट याचिका (आप.) क्रमांक – 197 / 2014

जगदीश

..... याचिकाकर्ता (गण)

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन

.....प्रत्यर्थी (गण)

निर्णय

न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता,

1. याचिकाकर्ता जगदीश पर उसकी पत्नी और पांच बच्चे की हत्या का विचारण किया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 24.04.2006 द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और मृत्युदंड दिया गया। उसने एक अपील पेश की जिसे उच्च न्यायालय ने 27.06.2006 को खारिज किया और मृत्युदंड की पुष्टि की। इसके बाद, उसने इस न्यायालय में अपराधिक अपील पेश की और निर्णय दिनांक 18.09.2009 के द्वारा पुनः मृत्युदंड की पुष्टि की।
2. याचिकाकर्ता ने जेल प्रशासन के समक्ष दया याचिका 13.10.2009 को पेश की जिसे भारत के राष्ट्रपति ने 16.07.2014 को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने दया याचिका के खारिजी के विरुद्ध रिट याचिका (आप.) क्रमांक [197 / 2014](#) पेश की और मुख्य आधार लिया गया की दया याचिका निर्णित करने में लगभग पाँच वर्षों की देरी हुई और यह खुद मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित करने का आधार है। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने पुनर्विलोकन याचिका क्रमांक [591 / 2014](#) भी पेश की जिसमें इस न्यायालय के निर्णय दिनांक

18.09.2009 के पुनर्विलोकन को गुण-दोष और अपराधिक अपील क्रमांक [338/2007](#) में सजा के प्रश्न दोनों पर चाहा है। इसलिये यह मामला इस पीठ के समझ पेश है।

3. शुरुआत में हम कहते हैं कि हम इस पुनर्विलोकन याचिका को मामले के गुणदोष पर सुनने के इच्छुक नहीं हैं। तीन न्यायालय द्वारा तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि वह याचिकाकर्ता ही था जिसने अपनी पत्नी एवं पाँच बच्चों की हत्या की। हमने याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का अवलोकन किया और हमें पहले लिये गये विचार से भिन्न विचार लेने का कोई कारण नहीं मिला।

4. हम केवल इस मुद्दे से निपट रहे हैं कि क्या मृत्युदंड को बरकरार रखा जाना चाहिए या नहीं? रिट याचिका में यह विनती की गई है कि दया याचिका को निर्णित करने में देरी और कानूनी कार्यवाही में देरी ही मृत्युदंड को वापस लेने के लिए काफी है। पुनर्विलोकन याचिका में कुछ अन्य तर्क लिये गए हैं। यह विनती की गई है कि यह मामला विरलतम में विरले की श्रेणी में नहीं आता है; यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामला है; याचिकाकर्ता जगदीश मानसिक बीमारी से पीड़ित था; याचिकाकर्ता को लगभग 14 वर्षों तक कैद में रखा गया है और इस स्तर पर मृत्युदंड का निष्पादन वस्तुतः दो सजाएँ थोपना होगा – आजीवन कारावास की सजा और फिर मृत्युदंड

5. **दया याचिका से निपटने में देरी :**

इस न्यायालय ने वी. श्रीहरण उर्फ मुर्गन विरूद्ध भारत संघ और अन्य¹ में अभिनिर्धारित किया कि इस न्यायालय ने मृत्यु दण्ड को अजीवन कारावास में कम करने के लिए मृत्यु दण्ड के निष्पादन में अनुचित, अयोग्य और अतार्किक विलंब को एक मान्य परिस्थिति के रूप में मान्यता दी है। न्यायालय ने हांलाकि यह अभिनिर्धारित किया है कि क्या विलंब अतार्किक है या नहीं, यह प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों से सराहना चाहिए। श्रीहरण के मामले में दया याचिका के निराकरण में पाँच साल और एक महीने का विलंब था और इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया कि :—

“17. दया याचिका के निराकरण में अत्याधिक विलंब, मृत्यु दण्ड के निष्पादन की प्रक्रिया को मनमाना, सन्की और अनुभवहीन बनाता है और इसलिए निष्पादन अयोग्य है। इससे अलावा, दया याचिका के निराकरण में अत्याधिक देरी से उत्पन्न ऐसे कारावास न्यायालय के द्वारा दी गई सजा से परे है और इस हद तक विधितर और अत्याधिक है।

1 (2014) 4 SCC 242

इसलिए सर्वोच्च संविधानिक प्राधिकारियों को संविधानिक मर्यादा से बाध्यकर होते हुए अनुच्छेद 72/161 के भीतर शक्तियों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए और उनके समक्ष दायर की गई दया याचिकाओं का निराकरण त्वरित तरीके से करना चाहिए।

18.

19. इससे पहले की हम उपरोक्त वर्णित तर्क का जवाब दे, यह प्रासंगिक है कि दया याचिका के निराकरण में विलंब के मामलों में जिस प्रारंभिक आधार पर अनुतोष दिया गया और यह कि ऐसा विलंब निष्पक्ष उचित और तार्किक प्रक्रिया की आवश्यकता का उल्लंघन करती है। इसके होते हुए भी और इसके द्वारा स्वतंत्र पीड़ा जो कारित होती है, विलंब मृत्युदण्ड के निष्पादन की प्रक्रिया को अनुचित, अविवेकी, मनमाना और मनमौजी बनाता है और जिसके चलते संविधान के अनुच्छेद-21 के अंतर्गत प्रदत्त की गई सम्यक प्रक्रिया का उल्लंघन करती है और ऐसे मामले में अमानवीय प्रभाव माना जाता है। इस संदर्भ में पूर्व में इस न्यायालय ने दया याचिकाओं के निराकरण के लिए आवश्यक उचित समय के अतिरिक्त बन्दीकरण को भी मान्यता दी है और निष्पादन के लिए तैयारी, अनुच्छेद-21 के अंतर्गत दोषी को प्रदत्त, सम्यक प्रक्रिया का उपहास करती है जो प्रत्येक बंदी को उसकी आखिरी सांस तक अंतर्निहित होती है।”

परिणामस्वरूप, न्यायालय ने मृत्युदण्ड की सजा को अजीवन कारावास में लघुत्तर किया।

6. अजय कुमार पाल विरुद्ध भारत संघ और अन्य² में यह न्यायालय एक प्रकरण से निपट रहा था, जहां दया याचिका के निपटारे में तीन वर्ष और दस महीने का विलंब था। इस प्रकरण में यह भी स्वीकृत था कि इस न्यायालय द्वारा मृत्युदण्ड की पुष्टि के बाद याचिकाकर्ता को एकांत कारावास में रखा गया था। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि दया याचिका के निराकरण में अत्यधिक विलंब और ऐसी लंबी अवधि के लिए एकल कारावास के संयुक्त प्रभाव, याचिकाकर्ता कि पोषित स्वतंत्रता से वंचित करने का कारण बना और इसलिए मृत्युदण्ड की सजा को अजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित कर दिया गया।

7. जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है घटना दिनांक 19.08.2005 की रात के दरमियान घटित हुई। विचारण न्यायालय ने विचारण तेजी से पूर्ण किया और 24.04.2006 को अपना फैसला सुना दिया। उच्च न्यायालय ने दो माह के भीतर दिनांक 27.06.2006 को सजा की पुष्टि कर दी, और इस न्यायालय ने दिनांक 18.09.2009 को अपील खारिज कर दी। याचिकाकर्ता ने जेल प्राधिकारियों के माध्यम से दिनांक 13.10.2009 को भारत के राष्ट्रपति और

2 (2015) 2 SCC 478

मध्यप्रदेश के राज्यपाल को संबोधित करते हुए एक दया याचिका दायर की। इस आवेदन को मध्यप्रदेश के प्राधिकारियों ने चार साल से अधिक समय बाद दिनांक 15.10.2013 को गृह मंत्रालय को प्रेषित की। तदुपरांत गृह मंत्रालय ने दिनांक 20.11.2013 को मध्यप्रदेश शासन से कुछ अभिलेख मंगवाया। इन दस्तावेजों को मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 12.12.2013 को प्रदान कर दिया। दिनांक 02.04.2014 को फाईल को भारत के राष्ट्रपति की ओर प्रेषित किया। इस फाईल को पुनर्विचार के लिए गृह मंत्रालय को वापस कर दिया। दिनांक 07.07.2014 को इसे भारत के राष्ट्रपति को दुबारा प्रस्तुत किया और अंततः इस दया याचिका को दिनांक 16.07.2014 को अस्वीकृत कर दिया गया था।

8. जहाँ तक भारत सरकार या भारत के राष्ट्रपति के सचिवालय का संबंध है, दया याचिका को निपटाने में कोई देरी नहीं की गई और इसे तेजी से निपटाया गया। हालाँकि, मध्यप्रदेश शासन ने इस दया याचिका को अग्रप्रेषित करने में 4 वर्ष से अधिक की देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है।

9. हम यह देखने के लिए विवश हैं कि वह मध्यप्रदेश शासन की ओर से न केवल एक लंबा, अयोग्य और अस्पष्टीकृत विलंब था बल्कि मामले को बदतर बनाने के लिये मध्यप्रदेश शासन ने रिट याचिका में जवाबी शपथपत्र पेश करने की भी परवाह नहीं की जबकि 4 वर्ष पहले 18.11.2014 को सूचना जारी की गयी और सूचना की तामीली जारी होने के एक महीने के भीतर हो गई थी।

10. याचिका को अग्रप्रेषित करने में देरी पूरी तरह से अस्पष्ट है और यह न्यायालय 4 वर्ष से अधिक अस्पष्टीकृत विलंब का समर्थन नहीं कर सकता। हम यहां एक ऐसे व्यक्ति के मामले से निपट रहे हैं जिसको मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। एक व्यक्ति जिसे मृत्युदंड मिला हो उसके लिये दया याचिका अंतिम उम्मीद है। हर सुबह एक नई उम्मीद को जन्म देगी कि उसकी दया याचिका स्वीकार की जा सकती है। रात होते ही यह उम्मीद भी खत्म हो जाती है। दया याचिका के निराकरण में अयोग्य और अस्पष्टीकृत विलंब और फलस्वरूप अंत में मृत्युदंड के निष्पादन में वर्षों तक विलंब एक दूसरे प्रकार की सजा है जो न्यायालय ने पारित की है। इस न्यायालय ने कई बार यह अभिनिर्धारित किया कि उन मामलों का निराकरण जल्द से जल्द करना चाहिये जहाँ मृत्युदंड का निष्पादन किया जाना है और यदि दया याचिका 4 वर्षों तक अग्रप्रेषित न की गई हो और कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत न किया गया हो तो हम अभिनिर्धारित करते हैं कि विलंब अयोग्य और अस्पष्टीकृत है।

11. हम न केवल दया याचिका के निराकरण में हुये विलंब के मुद्दे से निपट रहे हैं। याचिकाकर्ता अबतक लगभग 14 वर्षों तक सलाखों के पीछे रहा। यह भी एक कारण है जो विचार में लिया जाना चाहिये।

12. मृत्युदंड एक अपवाद है और इसे विरलतम से विरले मामले में दिया जाना चाहिये। मामले की समस्त परिस्थितियों पर विचार करते हुये, मध्यप्रदेश राज्य द्वारा दया याचिका को अग्रेषित करने में 4 वर्ष के अस्पष्टीकृत विलंब जिससे दया याचिका के निराकरण में लगभग 5 वर्षों का विलंब हुआ सम्मिलित है और यह तथ्य की याचिकाकर्ता लगभग 14 वर्षों तक कैद में रहा, हमारी यह राय है कि अपराध की क्रूर प्रकृति के होते हुये भी यह मामला मृत्युदंड निष्पादन करने के लिये उचित नहीं है और हम तदनुसार मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित करते हैं। हालाँकि, अपराध की प्रकृति एवं यह तथ्य की 6 निर्दोष जीवन समाप्त हुए को ध्यान में रखते हुए हम निर्देश देते हैं कि इस मामले में आजीवन कारावास का मतलब याचिकाकर्ता का संपूर्ण शेष जीवन होगा और उसकी मृत्यु तक उसे रिहा नहीं किया जायेगा। पुनर्विलोकन याचिका के साथ रिट याचिका आंशिक रूप से उपरोक्त शर्तों में आंशिक रूप से स्वीकृत की जाती है और तदनुसार निराकरण किया जाता है। लंबित आवेदन (ओं) यदि कोई हो तो वह निराकृत है।

..... न्यायमूर्ति

(एन वी रमना)

..... न्यायमूर्ति

(दीपक गुप्ता)

..... न्यायमूर्ति

(इंदिरा बनर्जी)

नई दिल्ली

21 फरवरी 2019